

प्रेषक,

एस. राजू,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,  
हल्द्वानी-नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-01.

देहरादून, दिनांक 27 जुलाई, 2015.

विषय: उत्तराखण्ड के बौने व्यक्तियों को आर्थिक सहायता योजना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में बौने व्यक्ति समाज की मुख्य धारा से लगभग अलग रहते हैं। इसका मुख्य कारण उनके जीवन-यापन हेतु उचित व्यवस्था न होने, आर्थिक रूप से अत्यन्त कमजोर होने, रोजगार के साधन न होने तथा उन्हें आर्थिक सहायता दिए जाने हेतु पृथक से कोई व्यवस्था न होना है।

2. बौने व्यक्ति को समाज के साथ तथा सामाजिक परिवेश में अपने जीवन-यापन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, अतः उत्तराखण्ड राज्य के बौने व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से ऐसे बौने व्यक्तियों को, जिनकी ऊँचाई 04 फिट से कम हो तथा जिनकी आयु 21 वर्ष अथवा उससे अधिक हो, को रुपये 800/- प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. उक्त नवीन योजनान्तर्गत पात्र व्यक्तियों का चयन किए जाने हेतु वही प्रक्रिया अपनायी जाएगी, जो "विकलांग भरण-पोषण अनुदान योजना" के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों के चयन हेतु अपनाई जाती है। नवीन योजना हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

4. उक्त नवीन योजना हेतु पात्र अभ्यर्थी से उनकी आयु के सम्बन्ध में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अभिलेखीय प्रमाण अवश्य प्राप्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी की ऊँचाई के सम्बन्ध में सम्बन्धित सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही अपनी सहमति प्रदान की जाएगी।

5. यदि योजना के संचालन/क्रियान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो इस सम्बन्ध में शासन का मार्गदर्शन/निर्देश प्राप्त किए जाने आवश्यक होंगे।

7



6. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-863/XXVII(1)/2015, दिनांक 23.07.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस. राजू)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-~~2879/19~~ (1)/XVII-1/2015-18(वि.क.)/2015-TC, तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वित्त अनुभाग-01, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(पी.एस. जंगपांगी)  
सचिव।

४



प्रेषक,

एस. राजू,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,  
हल्द्वानी-नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-01.

देहरादून, दिनांक 27 जुलाई, 2015.

विषय: विकलांग भरण-पोषण अनुदान योजनान्तर्गत जन्म से विकलांग बच्चों को भी 18 वर्ष की आयु तक ₹500 प्रतिमाह भत्ता दिए जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में ऐसी निराश्रित विकलांग व्यक्तियों, जिनके जीवनयापन के लिए न तो कोई स्वयं का साधन है और न ही वे किसी प्रकार का परिश्रम करके अपना जीवनयापन कर सकते हैं, को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के उद्देश्य से विकलांग भरण-पोषण अनुदान योजना संचालित है, जिसके अन्तर्गत 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले और 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाता है।

2. वर्तमान में 18 वर्ष से कम आयु के विकलांग बच्चों को राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दिए जाने की कोई योजना संचालित नहीं है और उक्त आयु वर्ग के विकलांग बच्चों के पालन-पोषण में उनके अभिभावकों को अतिरिक्त कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, अतः विकलांग भरण-पोषण अनुदान योजना के अन्तर्गत जन्म से विकलांग बच्चों को भी 18 वर्ष की आयु तक ₹500/- प्रतिमाह भत्ता दिए जाने की श्री राज्यपाल महोदय एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. उक्त भत्ते का भुगतान विकलांग बच्चे के अभिभावक के बैंक खाते में किया जाएगा। आयु सीमा, भत्ते की धनराशि और भुगतान की प्रक्रिया के अतिरिक्त विकलांग भरण-पोषण अनुदान योजना की अन्य प्रक्रियाएं/नियम यथावत् रहेंगे। विकलांग भरण-पोषण अनुदान योजना के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

4. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-862/XXVII(1)/2015, दिनांक 23.07.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस. राजू)  
अपर मुख्य सचिव।



संख्या-२४४ (1)/XVII-1/2015-06(91)/2006, तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वित्त अनुभाग-01, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,



(पी.एस. जंगपांगी)

सचिव।